लोक संपर्क कार्यालय

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

समाचार पत्र का नाम दैनिक भास्कर

दिनांक 20.2.2020 पृष्ठ सं. 3 कॉलम 5-7

गांव स्तर पर भी मिट्टी जांच के लिए बनेंगी लैब, रोजगार के अवसर मिलेंगे : कैलाश

भास्कर न्यूज़| हिसार

अगले पांच सालों में ब्लॉक स्तर पर आदर्श गांव विकसित किए जाएंगे। जिनमें मृदा परीक्षण रिपोर्ट आधारित मृदा मानचित्र तैयार होंगें और ग्रामस्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगें।

यह बात भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि कही। वह हकृवि के कृषि महाविद्यालय में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में अपना संबोधन दे रहे थे। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं तथा नई-नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। यह योजना भी उसी क्रम का एक हिस्सा है। उन्होंने बजट का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 से पहले कभी भी कृषि का बजट 30 हजार करोड़ से ज्यादा नही रहा। लेकिन अब इस सरकार ने बजट को बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपए किया है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति डॉ केपी सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय व राज्य का कृषि विभाग कदम से कदम मिलाकर किसानों के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि जब गूगल ने गूगल मैप सेवा शुरू की थी तो लोग इसका मजाक उडाते थे, लेकिन अब लोग गूगल मैप की मदद से अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार आने वाले समय में मृदा के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी मोबाईल फो- में उपलब्ध होगी। प्रो. सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय नौ लाख किसानों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय में स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला निरंतर कार्य कर रही हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने आधुनिक सॉयल टैस्टिंग वैन का भी उदघाटन किया जो गांव गांव जाकर मृदा परीक्षण करेंगी। कार्यक्रम के दौरान हकृवि के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ हुडडा और अधिकारीगण उपस्थित रहे।

एचएयू में किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चोधरी, साथ में है वीसी डॉ. केपी सिंह व अन्य।

लोक संपर्क कार्यालय
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

समाचार पत्र का नाम: अमर उजाला
दिनांक: 20.2.2020 पृष्ठ सं. 6 कॉलम 3-5

किसान बोले-मंत्री जी, मृदा हेल्थ कार्ड को अधिकारी केवल औपचारिकता बता रहे, कहते हैं खुद ही लेकर आओ सैंपल

एचएयू में कार्यशाला में मंच पर उपस्थित कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व अन्य। - अमर उजाला

अमर उजाला ब्यूरो

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में बुधवार को सॉयल हेल्थ कार्ड को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में वैज्ञानिकों की प्रस्तुति के दौरान ही किसान समस्याएं बताने लगे तो कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने भाषण से पहले किसानों की समस्याएं सुनीं।

इस दौरान सदलपुर के एक किसान ने कहा कि मंत्री जी, वह कई बार मृदा सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए अधिकारियों के पास गया, लेकिन वे कहते हैं कि मृदा हैल्थ कार्ड केवल औपचाकिरता है, आप मिट्टी ले आओ हम देख लेंगे। जबकि हेल्थ कार्ड के लिए सैंपल विशेषज्ञों को ही लेने होते हैं। इस तरह बिना तरीके के मृदा हेल्थ कार्ड बनाने का क्या फायदा है। वहीं, सिरसा के मोचीवाली गांव के एक किसान ने कहा कि उन्हें 2018 में बीमा क्लेम मिलना था, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। इस दौरान राज्यमंत्री ने सभी समस्याओं को नोट किया और मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

बीमारी का हो प्रकोप तो भी मिले बीमा क्लेम :फतेहाबाद के हसंगा गांव के किसान उदयसिंह ने कहा कि फसल बीमा करवाया जा रहा है, तो किसानों को बरसात, आंधी, ओले, सूखा आदि का ही क्लेम मिलता है। जबकि कई बार ऐसी बीमारी आ जाती है, जिससे पूरी की पूरी फसल ही खत्म हो जाती है। तो फसलों की बीमारियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए और उनका बीमा क्लेम मिलना चाहिए। इस पर राज्यमंत्री ने कहा कि इस पर आगामी बैठक में फिर से मंथन किया जाएगा। सदलपुर के किसान ने 12 माह पानी मिलने की मंजूरी के बाद भी पानी नहीं मिलने की शिकायत की तो राज्यमंत्री ने किसान को तुरंत लिखित शिकायत देने को कहा।

सिवानी के पास गुरेरा गांव से आए एक किसान ने कहा कि पानी की कमी और आंधी व अन्य नुकसान से बचाने के लिए एप्पल बेरी जैसी फसलों के बीमा करवाए जाने की मांग की। इस दौरान एक किसान ने प्लास्टिक की प्लेट में मिले खाने की भी शिकायत की। हालांकि इस पर विवि के अधिकारियों ने कहा कि ये प्लेट डिग्रेडेबल हैं।

एचएयू में आयोजित कार्यशाला में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री के सामने रखी समस्याएं

10 हजार फार्मर प्रोड्यूजर आर्गेनाइजेशन होंगे स्थापित

राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि 2014 से अब तक वर्ष कृषि बजट बढ़ रहा है। पिछले वर्ष यह एक लाख 37 हजार करोड़ था तो इस बार बढ़ाकर एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड में अब डेढ़ लाख रुपये के लोन के लिये कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नही होगी। उन्होंने किसानों के लिए चार चीजें कम लागत, उन्नत बीज, भण्डारण व बाजार को मूलभूत आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि नए बजट में सरकार ने 10 हजार फार्मर प्रोड्यूजर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सरकार हर महीने 30 हजार रुपये एक सीऐ रखने व 5-6 हजार अन्य खर्चों के लिए देगी।

हरियाणा में पिछले दो वर्ष में बने 40 लाख से अधिक मृदा कार्ड

केंद्र में संयुक्त सचिव तरसेम चंद ने बताया कि देश में 2015-17 में 10 करोड़ 74 लाख और 2017-19 में 11 करोड़ 74 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये। वहीं, हरियाणा में 2015-17 में 42 लाख 27 हजार और 2017-19 में 40 लाख 58 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये।

लोक संपर्क कार्यालय
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

समाचार पत्र का नाम अमर उजाला
दिनांक 20.2.2020 पृष्ठ सं. 6 कॉलम 3-5

किसान बोले-मंत्री जी, मृदा हेल्थ कार्ड को अधिकारी केवल औपचारिकता बता रहे, कहते हैं खुद ही लेकर आओ सैंपल

एचएयू में कार्यशाला में मंच पर उपस्थित कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व अन्य। - अमर उजाला

अमर उजाला ब्यूरो

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में बुधवार को सॉयल हेल्थ कार्ड को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में वैज्ञानिकों की प्रस्तुति के दौरान ही किसान समस्याएं बताने लगे तो कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने भाषण से पहले किसानों की समस्याएं सुनीं।

इस दौरान सदलपुर के एक किसान ने कहा कि मंत्री जी, वह कई बार मृदा सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए अधिकारियों के पास गया, लेकिन वे कहते हैं कि मृदा हैल्थ कार्ड केवल औपचाकिरता है, आप मिट्टी ले आओ हम देख लेंगे। जबकि हेल्थ कार्ड के लिए सैंपल विशेषज्ञों को ही लेने होते हैं। इस तरह बिना तरीके के मृदा हेल्थ कार्ड बनाने का क्या फायदा है। वहीं, सिरसा के मोचीवाली गांव के एक किसान ने कहा कि उन्हें 2018 में बीमा क्लेम मिलना था, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। इस दौरान राज्यमंत्री ने सभी समस्याओं को नोट किया और मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

बीमारी का हो प्रकोप तो भी मिले बीमा क्लेम :फतेहाबाद के हसंगा गांव के किसान उदयसिंह ने कहा कि फसल बीमा करवाया जा रहा है, तो किसानों को बरसात, आंधी, ओले, सूखा आदि का ही क्लेम मिलता है। जबकि कई बार ऐसी बीमारी आ जाती है, जिससे पूरी की पूरी फसल ही खत्म हो जाती है। तो फसलों की बीमारियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए और उनका बीमा क्लेम मिलना चाहिए। इस पर राज्यमंत्री ने कहा कि इस पर आगामी बैठक में फिर से मंथन किया जाएगा। सदलपुर के किसान ने 12 माह पानी मिलने की मंजूरी के बाद भी पानी नहीं मिलने की शिकायत की तो राज्यमंत्री ने किसान को तुरंत लिखित शिकायत देने को कहा।

सिवानी के पास गुरेरा गांव से आए एक किसान ने कहा कि पानी की कमी और आंधी व अन्य नुकसान से बचाने के लिए एप्पल बेरी जैसी फसलों के बीमा करवाए जाने की मांग की। इस दौरान एक किसान ने प्लास्टिक की प्लेट में मिले खाने की भी शिकायत की। हालांकि इस पर विवि के अधिकारियों ने कहा कि ये प्लेट डिग्रेडेबल हैं।

एचएयू में आयोजित कार्यशाला में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री के सामने रखी समस्याएं

10 हजार फार्मर प्रोड्यूजर आर्गेनाइजेशन होंगे स्थापित

राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि 2014 से अब तक वर्ष कृषि बजट बढ़ रहा है। पिछले वर्ष यह एक लाख 37 हजार करोड़ था तो इस बार बढ़ाकर एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड में अब डेढ़ लाख रुपये के लोन के लिये कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नही होगी। उन्होंने किसानों के लिए चार चीजें कम लागत, उन्नत बीज, भण्डारण व बाजार को मूलभूत आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि नए बजट में सरकार ने 10 हजार फार्मर प्रोड्यूजर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सरकार हर महीने 30 हजार रुपये एक सीऐ रखने व 5-6 हजार अन्य खर्चों के लिए देगी।

हरियाणा में पिछले दो वर्ष में बने 40 लाख से अधिक मृदा कार्ड

केंद्र में संयुक्त सचिव तरसेम चंद ने बताया कि देश में 2015-17 में 10 करोड़ 74 लाख और 2017-19 में 11 करोड़ 74 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये। वहीं, हरियाणा में 2015-17 में 42 लाख 27 हजार और 2017-19 में 40 लाख 58 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये।

लोक संपर्क कार्यालय
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

समाचार पत्र का नाम......अमर उजाला......
दिनांक....20.1.2020.... पृष्ठ सं.....6..... कॉलम.....1-6.....

ब्लॉक स्तर पर विकसित किए जाएंगे आदर्श गांव खेतों की मिट्टी के आधार पर बनेगा मानचित्र

एचएयू में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस वर्कशॉप में बोले संयुक्त सचिव, अगले पांच साल में योजना को पहनाएंगे अमलीजामा

अमर उजाला ब्यूरो

हिसार। अगले पांच वर्षों में ब्लॉक स्तर पर आदर्श गांव विकसित किए जाएंगे। इन गांवों में खेत की मिट्टी के परीक्षण रिपोर्ट पर आधारित मृदा मानचित्र तैयार होंगे, ताकि किसान अपनी मिट्टी के अनुरूप ही फसलें लगाएं और जब भी उनके खेत में किसी तत्व की कमी होगी तो उन्हें उस तत्व को पूरा करने के लिए बताया जाएगा। इसके लिए गांवों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे ग्रामीण युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इसके लिए योजना बनाई जा रही है। ये जानकारी बुधवार को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव तरसेम चंद ने दी। वे विश्वविद्यालय में आयोजित मृदा स्वास्थ्य कार्ड दविस पर आयोजित वर्कशॉप में बतौर वलिशिष्ट अतिथि शिरकत कर रहे थे। इससे पहले बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केपी सिंह ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान शिक्षा विस्तार निदेशक डॉ. आरएस हुड्डा और कृषि अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. आरके झोरड़ सहित विवि के वैज्ञानिक और प्रदेशभर से आए किसान मौजूद रहे।

संबोधित करते कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी।

एचएयू द्वारा गांव में चलाई जाने वाली सॉयल टेस्टिंग वैन। - अमर उजाला

मोबाइल बताएगा आपके खेत में किस चीज की कमी: कुलपति प्रो. सिंह ने बताया कि जब गूगल ने गूगल मैप सेवा शुरू की तो लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब लोग गूगल मैप की मदद से अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार आने वाले समय में आपके खेत की मृदा के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आपके मोबाइल फोन में उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट की मदद से मृदा में उपलब्ध पौषक तत्वों की मात्रा का पता लगाने व मृदा स्वास्थय को समझा जा सकेगा। इस पर काम हो रहा है, हालांकि समय लगेगा।

राज्य मंत्री बोले, पांच किसानों के फोन पर गांवों में पहुंचेगी वैन

कार्यक्रम से पहले राज्य मंत्री ने एक आधुनिक सॉयल टेस्टिंग वैन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि जिस गांव के पांच से अधिक किसान मृदा व पानी परीक्षण के लिए विश्वविद्यालय के कॉल सेंटर में फोन करेंगे, यह वैन उन गांवों में जाकर किसानों के खेत की मिट्टी व पानी की जांच करेगी और मौके पर ही रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर वैज्ञानिक बताएंगे कि वे कौन सी फसलें लगाएं और उनकी जमीन में किस तत्व की कमी है। इस दौरान राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की मदद से मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने, फसल उत्पादन बढ़ाने व किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

लोक संपर्क कार्यालय

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

समाचार पत्र का नाम पंजाब केसरी

दिनांक 20.2.2020 पृष्ठ सं. 2 कॉलम 1-6

किसान को है व्यापारी बनने की जरूरत : कैलाश

कहा- एक माचिस की कीमत तय हो सकती है तो फसल की क्यों नहीं, इस दिशा में किसानों को आगे आना होगा

मंच पर उपस्थित मुख्यातिथि व अन्य एवं कार्यक्रम में उपस्थित किसान।

हिसार, 19 फरवरी (राठी): चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के सभागार में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस पर एक दिवसीय कार्यशाला में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, कैलाश चौधरी ने कहा कि अब किसान को बेचारा नहीं बल्कि व्यापारी बनाने की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक माचिस बनाने वाला भी अपनी चीज की कीमत तय कर सकता है तो किसान क्यों नहीं अपनी फसल की कीमत तय करता है इसके लिए किसानों को फार्मर प्रोड्यूजर आर्गेनाइजेशन (एफ.पी.ओ.) स्थापित करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में देश में नए बजट में सरकार ने 10,000 फार्मर प्रोड्यूजर आर्गेनाइजेशन (एफ.पी.ओ.) स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है इसके लिए सरकार हर महीने 30,000 रुपए एक सी.ए. रखने व 5-6 हजार अन्य खर्चों के लिए देंगी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसान क्रैडिट कार्ड में अब 1,50,000 रुपए के लोन के लिए कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने किसानों के लिए 4 चीजें कम लागत, उन्नत बीज, भंडारण व बाजार को मूलभूत आवश्यकता बताया।

मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रेम-प्रसंग करने वाले एक युवक की मां का कलेजा चीरने वाली कथा से किसानों को समझाया कि हमें भारत माता यानी अन्न पैदा करने वाली उपजाऊ भूमि में जहर नहीं घोलना चाहिए। आर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए अगर किसान नहीं चेते आने वाले समय में हम बीमारियों से तो घिरेंगे ही, जमीन की उपजाऊ क्षमता भी खो देंगे।

हरियाणा में 40 लाख से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए

विशिष्ट अतिथि संयुक्त सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, तरसेम चंद ने कहा कि देश में 2015-17 में 10 करोड़ 74 लाख तथा 2017-19 में 11 करोड़ 74 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। वहीं हरियाणा में 2015-17 में 42 लाख 27 हजार तथा 2017-19 में 40 लाख 58 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए।

कुलपति ने माना, कई कार्डों में त्रुटियां, ठीक करेंगे

समारोह के अध्यक्ष कुलपति प्रो. के.पी. सिंह ने बताया कि आने वाले समय में आपके खेत की मृदा के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आपके मोबाईल फोन में उपलब्ध होगी। सैटेलाइट की मदद से मृदा में उपलब्ध पौषक तत्वों की मात्रा का पता लगाने व मृदा स्वास्थ्य को समझा जा सकेगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की मदद से मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने, फसलों उत्पादन बढ़ाने व किसानों की आमदनी बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इस दौरान कुलपति ने माना कि कई सोयल हैल्थ कार्डों में त्रुटियां हैं उन्हें ठीक किया जाएगा।

गांवों में जाएगी हकृवि की वैन

कार्यक्रम में किसानों को बताया कि विश्वविद्यालय की आधुनिक सॉयल टैस्टिंग वैन गांव-गांव जाकर मृदा परीक्षण करेगी व मौके पर ही रिपोर्ट देगी। इसके लिए किसी भी गांव के 5 से ज्यादा व्यक्तियों को फोन करके बताना होगा। इससे पहले मुख्यातिथि केन्द्रीय मंत्री ने आधुनिक सॉयल टैस्टिंग वैन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कुलपति प्रो.के.पी.सिंह, कृषि अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डा. आर.के. झोरड़, विस्तार शिक्षा निदेशक, डा. आर.एस. हुड्डा मौजूद रहे।

यह योजना है अगले 5 सालों में

- ब्लॉक स्तर पर आदर्श गांव विकसित किए जाएंगे।
- मृदा परीक्षण रिपोर्ट आधारित मृदा मानचित्र तैयार होंगे।
- ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी।

मंत्री के सामने किसानों ने रखी ये समस्याएं

- प्रगतिशील किसान रामभगत पंघाल ने मंत्री के सामने मांग उठाई कि किसानों के खेत तक मृदा जांच के लिए टीम पहुंचे ताकि किसान को खेत में ही रिपोर्ट मिल जाए।
- सदलपुर के किसान ने बताया, 5 साल से सॉयल हैल्थ कार्ड नहीं बन पाया है। सभी किसानों की जमीन के कार्ड बने।
- गुरेरा गांव के किसान ने बताया कि ऐपल, बेरी का बाग है लेकिन पानी की समस्या रहती है। बेरी के पेड़ का भी बीमा होना चाहिए।
- रतिया तहसील के किसान उदय सिंह ने बताया, पशुओं की तरह फसलों में होने वाली बीमारियों को लेकर भी बीमा हो।
- फतेहाबाद जिले के किसान रमेश ने बताया, अनार की खेती पर सबसिडी दी जाए। ऐसी सबसिडी राजस्थान में मिलती है।

लोक संपर्क कार्यालय
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

समाचार पत्र का नाम: हरिभूमि
दिनांक: 20.2.2020 पृष्ठ सं. 14 कॉलम 2-8

हकृवि के कृषि महाविद्यालय सभागार में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

किसान को व्यापारी बनने की जरूरत : चौधरी

- आधुनिक सॉइल टैस्टिंग वैन का उद्घाटन कर मुख्य अतिथि ने किसानों से जानी उनकी समस्याएं

हिसार। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि व अन्य। फोटो : हरिभूमि

हरिभूमि न्यूज ▸▸ हिसार

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि देश के किसान को व्यापारी बनने की जरूरत है। जिस दिन किसान व्यापारी बन गया तो फसल की कीमत किसान खुद तय करेगा।

यह बात केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बुधवार को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के सभागार में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव तरसेम चंद व विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केपी सिंह अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थें।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने आधुनिक सॉइल टैस्टिंग वैन का भी उद्घाटन किया तथा किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली।

डेढ़ लाख के लोन पर कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं

केंद्रीय मंत्री चौधरी ने घोषणा की कि किसान क्रेडिट कार्ड में अब 1,50,000 रुपये के लोन के लिए कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने किसानों के लिए चार चीजें कम लागत, उन्नत बीज, भण्डारण व बाजार को मूलभूत आवश्यकता बताया।

नए बजट में सरकार ने 10,000 एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सरकार हर महीने 30,000 रुपये एक सीए रखने व 5-6 हजार अन्य खर्चों के लिए देगी। सरकार और किसान इस प्रकार की योजनाओं पर मिलकर काम करेंगे तो किसान निश्चित ही अपने उत्पाद की कीमत खुद ही तय करेगा और किसान कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला बनेगा व भविष्य में किसान व्यापारी के रूप में पहचाना जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति अत्याधिक गंभीर है।

हकृवि व कृषि विभाग बैलों की जोड़ी : वीसी

समारोह के अध्यक्ष कुलपति प्रो. सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय व राज्य का कृषि विभाग कदम से कदम मिलाकर इस काम करते है जैसे बैलों की जोड़ी काम करती है, वे किसानों की समस्याओं को समझता है व उनका समाधान करने का प्रयास करते है। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट की मदद से मृदा में उपलब्ध पौषक तत्वों की मात्रा का पता लगाने व मृदा स्वास्थ्य को समझा जा सकेगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की मदद से मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने, फसलों उत्पादन बढ़ाने व किसानों की आमदनी बढाने में बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय कि आधुनिक सॉइल टैस्टिंग वैन गांव-गांव जाकर मृदा परीक्षण करेगी व मौके पर ही रिपोर्ट देगी।

भारत को पाक से नहीं देश में बैठे गद्दारों से खतरा

हिसार। केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि पुलवामा अटैक के बाद मोदी सरकार ने जिस तरह से सर्जीकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया, उसके बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से अब भारत को कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान को पता चला चुका है कि हिन्दुस्तान पहले वाला नही रहा। उन्होंने कहा कि आज हिन्दुस्तान को पाकिस्तान की बजाय देश में बैठे गद्दारों से खतरा है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बुधवार को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस पर आयोजित वर्कशॉप में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशें लागू करने के सवाल पर कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की लगभग सभी सिफारिशों को मान लिया है और 99 फीसद पूरी भी हो चुकी है। जहां तक किसान के कर्जामाफी का सवाल है, स्वयं स्वामीनाथन भी कर्जामाफी के हक में नहीं थे। सरकार की कोशिश है कि देश का किसान कर्जा लेने वाला न बने बल्कि कर्जा देने वाला बने। किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के सवाल पर राज्यमंत्री ने कहा कि किसान आत्महत्या नहीं कर सकता। फिर भी किसान आत्महत्या करता है, तो इस तरह की घटना चिंताजनक है। मोदी सरकार का प्रयास है कि किसानों द्वारा आत्महत्या के आंकड़ों को नीचे लाया जा सके। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में किसान रेल शुरू की जाएगी। इसके अलावा भविष्य में देश के अंदर 10 हजार एफपीओ खोल जाएंगे।

आदर्श गांव विकसित करेंगे : संयुक्त सचिव

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव तरसेम चंद ने कहा कि देश में 2015-17 में 10 करोड़ 74 लाख तथा 2017-19 में 11 करोड़ 74 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। वहीं हरियाणा में 2015-17 में 42 लाख 27 हजार तथा 2017-19 में 40 लाख 58 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए।

अगले पांच वर्षों में ब्लॉक स्तर पर आदर्श गांव विकसित किए जाएंगे, जिनमें मृदा परीक्षण रिपोर्ट आधारित मृदा मानचित्र तैयार होंगे व ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएगी, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

यह रहे उपस्थित

इस अवसर पर कृषि अभियान्त्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता, डॉ. आर.के.झोरड़ ने स्वागत तथा विस्तार शिक्षा निदेशक, डॉ. आर.एस.हुड्डा ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, निदेशक, अधिकारीगण, वैज्ञानिकगण, सभी जिलों से आये किसान उपस्थित थे।

बिना कुछ गिरवी रखे किसान ले सकते हैं डेढ़ लाख तक का लोन

हकृवि में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस पर कार्यशाला में बोले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी

जागरण संवाददाता, हिसार : डेढ़ लाख रुपये तक का लोन के लिए किसानों को कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड में अब 1,50,000 रुपये तक का लोन बिना कुछ गिरवी रखे मिल सकता है। यह जानकारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के सभागार में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस पर एक दिवसीय कार्यशाला में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, कैलाश चौधरी ने दी। वह कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए चार चीजें कम लागत, उन्नत बीज, भंडारण व बाजार की मूलभूत आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि नए बजट में सरकार ने 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन (एफपीओ) स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है इसके लिए सरकार हर महीने 30,000 रुपये एक सीए रखने व 5-6 हजार अन्य खर्चों के लिए देगी। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से समस्या व सुझाव मांगे व उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में संयुक्त सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, तरसेम चंद व विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केपी सिंह अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने आधुनिक मृदा टेस्टिंग वैन का भी उद्घाटन किया तथा किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय सभागार में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस पर कार्यशाला के दौरान संबोधित करते कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और मंच पर मौजूद कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह। • जागरण

भविष्य में किसान व्यापारी के रूप में पहचाना जाएगा

केंद्रीय मंत्री कैलाश ने कहा कि सरकार और किसान इस प्रकार की योजनाओं पर मिलकर काम करेंगें तो किसान निश्चित ही अपने उत्पाद की कीमत खुद ही तय करेगा और किसान कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला बनेगा व भविष्य में किसान व्यापारी के रूप में पहचाना जाएगा। अगले पांच वर्षों में ब्लॉक स्तर पर आदर्श गांव विकसित किए जाएंगे, जिनमें मृदा परीक्षण रिपोर्ट आधारित मृदा मानचित्र तैयार होंगे व ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएगी। जिससे कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

कृषि के लिए अबकी बार 1,50,000 करोड़ का बजट

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, कैलाश चौधरी कैलाश चौधरी ने कहा कि इस योजना का शुभारंभ 5 वर्ष पूर्व वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में किया था। प्रधानमंत्री किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं तथा नई-नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। यह योजना भी उसी क्रम का एक हिस्सा है। उन्होंने बजट का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 से पहले कभी भी कृषि का बजट 30 हजार करोड़ से ज्यादा नही रहा, वहीं गत वर्ष कृषि मद का सालाना बजट 1,37,000 करोड़ रूपये था जो कि बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रूपये किया गया है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के आंकड़े

सेशन	कार्ड वितरित
2015-17	10 करोड़ 74 लाख वितरित
2017-19	11 करोड़ 74 लाख वितरित

हरियाणा में इतने मृदा कार्ड हुए वितरित

सेशन	कार्ड वितरित
2015-17	42 लाख 27 हजार
2017-19	40 लाख 58 हजार

9 लाख किसानों से जुड़ा हुआ है विश्वविद्यालय

कुलपति प्रो. सिंह ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की मदद से मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने, फसलों का उत्पादन बढ़ाने व किसानों की आमदनी बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय नौ लाख किसानों से जुड़ा हुआ है व विश्वविद्यालय में स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि विज्ञान केन्द्रों में स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला व मोबाइल मृदा जांच प्रयोगशाला द्वारा मृदा परीक्षण किए जा रहे हैं व किसानों को मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही खादों व उर्वरकों के इस्तेमाल की सिफारिश की जाती है।

प्याज के बढ़े दाम को लेकर करवाई जा रही जांच

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के सभागार में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस पर कार्यशाला में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, कैलाश चौधरी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने विभिन्न जिलों से आए किसानों से समस्या व सुझाव मांगे व समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रगतिशील किसानों की जानी समस्याएं और सुझाव भी मांगे

केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से बातचीत के कुछ अंश

- **सवाल :** किसानों के लिए क्या चुनौतियां है।

जवाब : किसानों के साथ हमारे सामने भी कई चुनौतिया है। 2022 तक किसानों की इनकम दौगूना करने का लक्ष्य है। किसानों को उन्नत किस्म के बीज, भंडारण और बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है। बजट में भी 16 टारगेट है जिनमें वेयर हाउस, किसान रेल प्रारंभ की जाएगी। बजट भी एक लाख 50 हजार करोड़ किया गया है।

- **सवाल :** किसान संगठन अभी भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर क्यों अटका है।

जवाब : स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को माना गया है। किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की 95 फीसदी मांगों पर काम किया गया है। किसान कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बने के उद्धेश्य को लेकर काम किया जा रहा है।

- **सवाल :** किसान आज भी आत्महत्या करने को मजबूर है।

जवाब : किसान आत्महत्या नही कर सकता है, चाहे राजस्थान का किसान हो या महाराष्ट्र का या हरियाणा का हो किसान हमेशा मजबूत रहा है। सरकार प्रयास कर रही है आने वाले समय में आत्महत्या का आंकड़ा कम हो। ऐस कोई समाचार मिलता है तो यह चिंताजनक है। इसे दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

- **सवाल :** प्याज के दाम लगातार बढ़े है।

जवाब : इसके लिए कोल्ड स्टोरेज हाउए बनाए जा रहे है। वहीं मामले की जांच भी की जा रही है। अगर किसान फसलों को सुरक्षित रख सकेंगे तो प्याज और अन्य फसलों को स्टोर कर पाएंगे।

किसानों ने अपनी समस्याएं बताई और कई सुझाव भी दिए

- भिवानी के सिवानी से आए एक किसान ने कहा कि उसने नई तकनीक से एप्पल बेरी की खेती की थी। लेकिन आंधी आई और फसल खराब हो गई। इस किसान ने फलदार फसलों का बीमा शुरू करने की मांग रखी।
- एक किसान ने सुझाव दिया कि उन्हें इस कार्यशाला से पहले बाहर प्लास्टिक की थाली में खाना दिया गया है जिससे सेहत खराब होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर कुलपति ने कहा कि यह प्लास्टिक नष्ट कर सकते है। इसलिए इसका प्रयोग किया गया है।
- फतेहाबाद से आए किसान उदय ने समस्या बताई कि बरसात और ओलावृष्टि से फसल खराब होने पर तो बीमा मिलता है, लेकिन फसलों में कोई बीमारी लगने पर बीमा नहीं दिया जाता।
- सिरसा से आए रघुबीर ने कहा कि उसका मोचीवाली जमीन का बीमा 2018 में किया गया था। लेकिन इसे किसी दूसरी जगह पर दिखा दिया गया। सीएम विंडो व डीसी को मामले की शिकायत कर चुके है। लेकिन बीमा नहीं मिला, बैंक वालों ने टैक्निकल गलती होने की बात कही।
- फतेहाबाद से रमेश ने पूछा कि होर्टीकल्चर में कई जगहों पर नमकीन पानी में अनार की खेती हो रही है। लेकिन अन्य फसलों पर तो सब्सिडी मिल रही है, लेकिन अनार पर सब्सिडी नहीं मिल रही।
- एक किसान ने सुझाव दिया कि वह पराली मिक्स खेती कर रहे है। वह बासमती 1509 किस्म में पराली को शामिल करके खेतों में डालते है। जो अच्छी भी रहती है और पराली जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अन्य किसान भी ऐसा कर सकते है।
- दीपक नाम के किसान ने सुझाव दिया की डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन 5 दिन के कोर्स हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में करवाए जा रहे है, इन्हें समयावधि को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि किसान इन कार्यों को अच्छे से सीख सके।

लोक संपर्क कार्यालय
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

समाचार पत्र का नाम........दैनिक भास्कर........
दिनांक....20.2.2020.... पृष्ठ सं.....6..... कॉलम.....2-5.....

वैज्ञानिक पद्धति से किसान करें चप्पन कद्दू का अच्छा उत्पादन

राकेश कुमार | गढ़ी बीरबल

मार्च-अप्रैल के महीनों में हरियाणा में गोल फल वाले चप्पन कद्दू की लंबे चप्पन कद्दू (जूचीनी) की तुलना में अधिक मांग रहती है। गोल फलदार चप्पन कद्दू से किसान अधिक आमदनी प्राप्त करता है। क्योंकि ये फसल बेमौसमी तैयार की जाती है। जिसका उपयुक्त बिजाई का समय अक्तूबर व नंवबर के महीने हैं। हरियाणा प्रांत में किसान दिसंबर से फरवरी के महीने में भी प्लास्टिक लो टनल(मिनिएचर प्लास्टिक की सुरंग) के प्रयोग से अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इसके अलावा अधिकतम फलत प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को अपनाकर किसान अपेक्षाकृत उत्पादन प्राप्त कर सकता हैं। पूर्व अध्यक्ष सब्जी विज्ञान विभाग हरियाणा कृषि विश्विद्यालय हिसार के प्रोफेसर सुरेश कुमार अरोड़ा ने बताया कि चप्पन कद्दू की खेती करने के लिए किसानों निम्नलिखित उपाय करने चाहिए।

प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग फसल के अंत तक बेहद जरूरी

चप्पन कद्दू उत्पादक ध्यान रखें चप्पन कद्दू की खेती करते हुए प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग उनके लिए बेहद जरूरी है। इससे फल पानी में गलते नहीं(फसल तुड़ाई उपरांत हानि)। मल्चिंग को जमीन के ऊपर बैड़ों के ऊपर बिछाते हैं। यह नीचे से काली और ऊपर से सिल्वर रंग की होती है। यह फसल की तोड़ाई के अंत तक बिछी रहती है । डॉक्टर अरोड़ा ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि प्लास्टिक मल्च बागवानी विभाग हरियाणा सरकार किसानों को अनुदान राशि भी देती है।

ड्रिप सिंचाई का उपयोग

चप्पन कद्दू की खेती ऊपर उठे बैडो पर की जाती है। किसानों को चाहिए वे एक बैड के ऊपर चप्पन कद्दू के पौधों की तीन कतारें सही ढंग से ले। साथ ही इन तीनों कतारों के बीच में दो ड्रिप लाईन (16 एमएम,1.25 एलपीएच) होनी चाहिए जिससे कि पानी की 80% तक बचत होगी। फल अच्छी गुणवक्ता चमकदार भूरे बालों के साथ व बेदागी पैदा होते हैं।

पौधों की बीमारियां, कीट एंव जड़ों के सूत्रकृमि रोगों से बचाव : चप्पन कद्दू के पौधों पर सूड़ोमोनाश, ट्राईकोड्रमा, बैसिलेशसब्तिलिस, बिवेरिया बाशीयाना, माईकोराईजा, पैसिलोमाइसिस लीलासिनस एंव वर्टीसिलियम नामक जैविक फफूंदनाशक एंव वनस्पतिक कीटनाशक दवाईयां जैसे कि नीम का तेल, नीम की खल व केचुआ खाद यानि वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। इनके छिड़काव से पौधों पर किसी भी प्रकार फफूंद, बैक्टिरिया जनित बीमारी, विषाणु रोगों का प्रकोप एंव पत्तें कुतरने वाले कीट, रस चूसने वाले कीट, पत्तों के नीचे सुंरग बनाने वाले कीट (लीफ माइनर) अल, चेपा, महुआ, सैमिलूपर कैटरपीलर(सूंड़ी) से बचाव होगा।